measures should be taken to save the weavers, their employment and the flourishing Mysore Silk Industry.

Demand to include the enumeration of Non-Resident Indians during the Census, 2011

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, the parameters for conducting the first phase of 2011 Census have been finalized by the Government. The 'House Listing and Housing Census' has already commenced from 1.4.2010 in various States and Union Territories.

As per the pre-fixed parameters, the total number of persons normally residing in the households is taken into account for assessing the data. While following this procedure, the Pravasi Indians, the NRIs, who are temporarily migrated to alien lands for livelihood, will not be counted in the Census. Being included in the Census data is very much important for every Indian. Presently, the whole country is eagerly looking to grant of voting rights to the NRIs. But due to technical grounds, the Election Commission has not yet accepted the proposal.

Including the names of the NRIs in the Census data is not technically difficult. They can be included as NRIs in the Census data. This inclusion will help them in many respects including the feeling of getting a patronage from the mother land. For availing a number of services rendered by the Government and the private agencies, the inclusion of name in the Census rolls is a basic necessity.

So, I request the hon'ble Chairman to consider this urgent necessity of the NRIs positively and direct the Government to take urgent necessary action.

Demand to resolve the problems to employees of Railways in the country

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, यह सर्वस्वीकृत है कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, किन्तु आज रेलवे में इतनी सारी गंभीर समस्याएं हैं कि अगर उन पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो मामला बिल्कुल बिगड़ जाएगा। जैसे, रेल पटरियों में नवीनीकरण का मुद्दा है। ऐसा आरोप है कि 2004 के बाद रेल पटरियों का नवीनीकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है और इन पर अधिक रेलगाड़ियों के चलने का सिलसिला चालू है। ऐसी स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

रेलवे को देश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना गया है। भारतीय रेल पर पिछले कई सालों से भर्ती के मामले में पीछे चलने का आरोप सामने आया है। ऐसा कहा जाता है कि अभी लगभग दो लाख पद रिक्त पड़े हैं। विशेषकर, समूह "घ" और समूह "ग" में ये रिक्तियां अत्यंत उत्कट हैं। इससे track maintenance से लेकर गाड़ी परिचालन तक, सभी कार्य बाधित हो रहे हैं।

महोदय, भारतीय रेल से संबंधित एक और गंभीर मामला यह है कि उसमें जो लगभग एक लाख रेलवे इंजीनियर्स कार्यरत हैं, वे वेतन विसंगतियों के शिकार हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक उनके प्रति न्याय नहीं हुआ है। रेलवे में यह विसंगति है कि ऐसे कई सारे डिग्री इंजीनियर्स हैं जो रोजगार की आवश्यकता हेतु श्रेणी-3 में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उनकी पदोन्नति न होने के कारण वे जिंदगी भर श्रेणी-3 में ही रह जाते हैं। जो मांग रेलवे इंजीनियर्स कई सालों से उठाते रहे हैं, उनके प्रति ध्यान न दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसी प्रकार, रेलकर्मियों के संघों की मान्यता हेतु चुनाव का मसला भी एक अत्यंत आवश्यक विषय है। यह चुनाव वर्ष 2007 में कई साल के संघर्ष के बाद गुप्त मतदान के जरिए संपन्न हुआ, फिर भी श्रम मंत्रालय को